other mechanism. 1 will co-operate with you fully.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think the Minister Sahib has given the entire policy for the future also. So, wc can go to Question No. 104. ***(Interruptions***)....आई नो इस पर किंसी और समय पर डिसकस करेगे । दो क्वेक्षन मे ही क्वेक्षन आवर खत्म हो रहा है । जिचकर जी आपने तो क्वेक्षन पूछ लिया?

Apprehension regarding rise in the prices of Urea

*104. SHRIMATI BASANTI SARMA:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA J1CHKAR:

Wil! the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is an apprehension amongst tanners that the prices of urea will be raised;

(b) if so, Government's proposal to eliminate this apprehension from the minds of farmes and

(c) the steps being taken to keep the prices of urea down?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) and (b) The price of urea has been increased by 10% with effect from 21.2.1997 for the present in order to reduce the imbalance in the application of NPK nutrients.

(c) The price of urea is already much lower compared to the decontrolled fertilizers. However, since the country's requirement of Urea is met through both indigenous production and imports, which is much costlier, any reduction in price of Urea is possible only if imports are avoided.

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Madam, a high-power committee headed by the noted economist, Shri Hanumantha Rao, was appointed to go into the entire gamut of the retention price mechanism of urea. When this question of hiking the price of urea by 10% had gone before the Cabinet Committee on Economic Affairs, a decision was deferred. An official spokesman of the Ministry said that there would be no hike in the price of urea until the Hanumantha Rao Committee gave its report. This was said on the 17th of February, 1997. On 17th February, an official spokesman of the other Ministry, that is, Mr. Ola's Ministry, said that there would be no increase in the price of urea and that the Cabinet had deferred a decision. On 21st February, they made an announcement that there would be an increase of 10% in the price of urea. Now what has happened in these four or five days necessitating this drastic decision?

श्री चतुरानन मिश्र : मैडम, माननीय सदस्या को कैबिनेट की जितनी जानकारी है उतनी शायद हम को नही है और हमारी लाचरी है कि हम रख भी नही सकते है। इसलिए इस पर मै कुछ नही कहूंगा। लेकिन मै एक बात कहना चाहता हूं कि हनुमंतराव कमेटी जो बनी है उसका दूसरा काम है। इसको भी देखेगी लेकिन उसका दूसरा काम है। मै बहुत ध्यान से सुन रहा था जब माननीय सदस्य-गण पूछ रहे थे कि प्राइवेट कंपनी को ज्यादा पैसा मिल रहा और वह ज्यादा लाभ उठा रहे है। मै इसको सुन रहा था। लेकिन हमको अधिकार नही था। अब अधिकार है और हम आपको कहना चाहते है। यह ठीक है कि जो कैपिटल रिलेटेड एक्स्पेडीचर होता है उसकी 100 परसेट कैपेसिटी होनी चाहिए। इसमें एक कंपनी ऐसी है, उसने अपनी कैपेसिटी 143 परसेंट दिखाई है और उस पर वह प्राइस लेता चला जा रहा है।

उपसभापति : **नाम लेने में कोई हर्ज नही है। वह पुरुष या महिला नही है।**

A company's name can be mentioned. You should not mention the names of those people who cannot defend themselves here.

श्री चतुरानन मिश्र : पुरुष और महिला वे तो सिर्फ हिन्दी में लागू होते है। संस्कृत में तीन जैडर होते है।

उपसभापति : तीसरे जैडर का नाम लेना अलाउड है।

श्री चतुरानन मिश्र : मै उस कंपनी का नाम कह देता हूं। नागार्जुन फर्टिलाइजर कंपनी। इसने दिखला दिया 143 परसेंट। अब इसमें क्या है, उसको उत्पादन के लिए अलग से दाम बढाकर देते है। अब अगर 143 पर पहूंच जाए तो अबसर्डिटी हो जाती है। लेकिन इसमें तय क्या है वह मै माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं। फर्टिलाइजर प्लांट में एक इन बिल्ट कैपेसिटी रहती है। वह एक्सीडेंटल है। जैसे अगर भूकम्प आ जाए तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए 5 प्रतिशत है टेम्प्रचर डाऊन हो जाए या अप हो जाए, ऐसा कर के करीब 18 प्रतिशत इनबिल्ट राव साहब की अध्यक्षता में वह कमेटी बनी है जो जांच करे (**व्यवधान**) अध्यक्ष या जो भी सोचिए वही है, वह जांच करेगी, उसका इससे संबंध नही था यह जो वस्तु है जिसके बारे में हमारे फर्टिलाइजर मंत्री महोदय ने कहा असंतुलित व्यवहार करने से भी खेत ऊसर हो रहा है, जो सायल की हेल्थ है वह बैडली अफेक्टेड हो रही है। पंजाब से ही रिर्पोट आई है और कुछ साइंटिस्टस ने हमारे पास रिर्पोट भेजी है कि यह एडवर्सिल अफेक्ट कर रहा है तो हमने बिना फाइनेशियल बर्डन किये हुए जितना रुपया यूरिया से लिया उतना रुपया हमने किसानों को दूसरी फर्टिलाइजर में दे दिया है। चूंकि यह प्रसारित हो रहा है इसलिए हमें इसको दोहरने की जरुरत नही है। अब उसी के संबंध में पूछा गया क्या कदम उठाया जा सकता है जिससे यूरिया का दाम सस्ता हो। यह आपके प्रश्न का अंश है। मै इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जो आयातित यूरिया है, उसका दाम ज्यादा है। उसका दाम पड़ता है हैडलिंग चार्ज लगा कर 8508 रुपये और जो अपने देश के अन्दर उत्पादन होता है उसका दाम पड़ता है 5600 रुपये। तो यह 3000 रुपये का फर्क दोनों में पड़ता है। रिटेशन प्राइस तो हम अलग से देते है। यदि हम देश में होने वाले उत्पादन को बढा दें तो हम इसे और सस्ता कर सकते है। इसलिए हम इस बात की कोशिश कर रहे है। हमारे फर्टिलाइजर के माननीय मंत्री जी इस बात के लिए बहुत उद्यत है कि जो फर्टिलाइजर प्लांट देश में बंद है उनको चालू करवा दें। अगर हम उसमें सफल हो जाते है तो 20-25 लाख टन और भी यूरिया अपने देश में उत्पादित हो जाएगा और आटोमेटिकली सबिस्डी भी कम हो जाएगी और दाम भी किसानो को सस्ता दे सकेंगे। यह जो बाहर से मंगवाते है अनिवार्य काराणो से,। इनके चलते हमें ज्यादा मूल्य चुकाना पड़ता है। यूरिया के मुतालिक यह मामला है। हम इसके प्रयास में है कि वह जल्दी से जल्दी चालू हो जाएं तो हम इसको कर सकेंगे। इसके इलावा और भी कारण है गैस का दाम है,

उनको हम देख रहे है। एक बात और कहना चाहता हूं। यह सही नही है कि पब्लिक सेक्टर के कारखाने को घाटा लगता है। देश के कोआप्रेटिव सेक्टर में इसको और कृभको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे है, जो आपका प्राइवेट सेक्टर भी नही दे रहा है। उनके जरिये कोशिश कर रहे है कि विदेशो में जहां फास्फोरिक एसिड है, जहां रॉक फॉसफेट है वहां ज्वाइंट सेक्टर में कारखाने खोल लें तो हम पर भार कम हो जाएगा। ईरान या दूसरे देश है, वह कर रहे है कि हमारे यहां आ कर आप कारखाने खोलिए। हम अपनी कम्पनियों को कहते है कि ज्वाइंट सेक्टर में खोलें। हमारा ख्याल है कि इसमें कुछ टाइम लगेगा। चार पांच वर्ष तो लग जाते है किसी भी चीज में। हम उस दिशा में आगे बढेंगे, जब हम अपने किसानों का सस्ता फर्टिलाइजर दे सकेंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Narendra Mohan.

DR. SHRIKANT RAM CHANDRA JICHKAR: I want to ask my second supplementary.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, you are not the original questioner.

श्री नरेन्द्र मोहन : धन्यवाद उपसभापति महोदय। कृषि मंत्री जी ने बताया कि जो यूरिया अपने देश में उत्पादित होता है उसकी कीमत कम है और विदेशों में ज्यादा है। इसलिए शायद आयातित यूरिया महंगा होता है। लेकिन एक बात मेरी जानकारी में यह है कि भारत में जो भी इस प्रकार के कारखाने यूरिया के है उनमें आधुनिकतम तकनीक और ज्ञान का प्रयोग नही होता है और जिस तकनीक का उत्पादन में प्रयोग होता है वह बहुत पुरानी है। इसके चलते अनेक कारखाने बंद हो चुके है। प्रधानमंत्री जी गोरखपुर गये थे। वहां पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि कारखाना चालू हो जाएगा । अब आप कहते है कि समय लगेगा, इसमें भी समय लगेगा। आखिर आप यह बताएं कि हमारे जो कारखाने है क्या उनमें आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग हो रहा है या नही हो रहा है और जो कारखाने बंद है, वह कब तक चालू हो जाएंगे। यह मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल है ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : एक ही सवाल पूछ लीजिए। समय नही है। यह जवाब दीजिए मंत्री जी।

श्री नरेन्द्र मोहन : इस सवाल का जवाब आने दीजिए। जुड़ा हुआ सवाल बाद मे। एक तो आ जाए। यह लम्ब जवाब है इस सवा

श्री चतुरानन मिश्र : जहां तक यह बात है कि आधुनिकतम है, आधुनिकतम शब्द तो सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन आधुनिक मशीनरी है। कोआपरेटिव सेक्टर में इफ्को और कृभको में। जो बंद और सिक कारखानों की बात आप कर रहे है उनका आउटमोडेड हो गया था। उनको जरुर माडर्नाइज करना है। उसमें हिदुस्तान फर्टिलाइजर है, एफ.सी. आई. है। ये दोनों है। उसकी तरफ प्रयास हो रहा है कि उनको चालू करें।

श्री नरेन्द्र मोहन : कब तक चालू हो जांएगे?

श्री चतुरानन मिश्र : कब तक हो जाएगा? यह कोई डिलीवरी है कि हम बता दें। कारखाना बनेगा तब होगा ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति :श्री नरेश यादव ...

श्री नरेन्द्र मोहन : दूसरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है...

उपसभापति : बैठिए ...(**व्यवधान**)... नाट टु यू। मिस्टर यादव...

श्री संजय निरुपम : पिछले दस सालों से वे कारखाने बंद है। पूछ रहे है कब तक शुरु किए जाएंगे तो उन्होंने डिलीवरी बता दी ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति ; एक सेकिड आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... आपको नही बुलाया है। यादव जी।

श्री संजय निरुपम : हम जानना चाहते है ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : आप बैठिए Please sit down. This is not the way.

श्री नरेश यादव : महोदया, मै आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री और माननीय उर्वरक मंत्री जी से यूरिया एवं अन्य उर्वरकों के बारे में जानना चाहता हूं। माननीय उर्वरक मंत्री जी ने यह बताया कि सेल्स टैक्स जो है उसका निर्धारण राज्य सरकारें करती है।, निश्चित तौर से उर्वरको पर सेल्स टैक्स राज्य सरकारें निर्धारित करती है। ऐसा हो जाता है कि कभी-कभी पड़ोसी राज्यों में कही टैक्स कम हो जाता है कही बगल के राज्यों में टैक्स ज्यादा हो जाता है और ठीक समय पर बोआई के समय या सिंचाई के समय यूरिया या अन्य उर्वरकों डी. ए.पी. या पोटाश में देश में मारा-मारी या हाहाकार मच जाता है और किसान इससे प्रभावित हो जाते है। जब हम चीनी का रेट पूरे देश में एक कर सकते है, गेहूं का रेट पूरे देश में एक कर सकते है वितरण का तो फिर क्या इन उर्वरकों की दर भी एक की जा सकती है जिससे कि किसानों में मारामारी न हो? धन्यवाद।

श्री एन.के.पी. साल्वे : गेहूं का रेट एक नही है।

श्री चतुरानन मिश्र : आपने तो दोनों मंत्रियों से पूछा है पहले किसको...

उपसभापति : दोनों बोल दीजिए It is a joint responsibility.

SHRI CHATURANAN MISHRA: He said that he was addressing it to both the *Mantris.* I did not want to encroach upon anybody's right.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुवेंदी :पंडित जी, बिहार का मामला है।

श्री चतुरानन मिश्र : यह बिहार का नही, यह सारे राष्ट्र का है। आप कहे यह तो शोभा नही देता है। दूसरे आदमी कहे। आप तो सारे भारत को नचाए है। इसलिए आप मत कहे।

श्री एन. के. पी. साल्वे : आप डिलीवरी करें।

श्री चतुरानन मिश्र : जो प्रश्न उन्होंने कहा है वह बहुत सही है, आलोचना सही है। लेकिन देश में लोग मांग करते है कि फ्री ट्रेड हो ...(**व्यवधान**)... जरा सुनिए। कहते है फ्री ट्रेड हो, पहले से तय हो गया। जब फ्री ट्रेड कर दिया तो कहते है दाम बांधो। दोनों बाते कैसे होगी। काहे यह पार्लियामेंट कहती है कि फ्री ट्रेड हो। जब आप एक बार कह दिए तब तो यह होगा कि लोग दाम बढाना शुरु करेंगे। हम तो उनकी मदद करते है। हम सब्सिडी भी नही देते है।

श्री एन. के. पी. साल्वे : बढाने मे?

श्री चतुरानन मिश्र : नही बढाने में तो नही देते है, घटाने के लिए देते है। बढाने वाला तो आपने फ्री ट्रेड कर दिया और यह बच्चा लेकर हम घूम रहे है। समझ लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री एन.के.पी. साल्वे : सब नाजायाज बच्चे आपके सुपुर्द है।

श्री चतुरानन मिश्र : यह इनका बेबी लेकर हम चल रहे है। अब ये ही लोग मांग करते है कि आप कंट्रोल क्यों नही करते है। दोनों बाते कैसे होगी सो बता दीजिए। तभी तो किसानों की मदद के लिए हम असिस्टेंस आपको दे रहे है?

श्री अजीत जोगी : बेबी आपको पंसद तो आ गया है ना?

श्री चतुरानन मिश्र : कम्पलशन है। उस बच्चे को हम अनाथ छोड़ कैसे दें।

श्री नरेन्द्र मोहन : एडाष्ट कर लीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र: हो सकता है एडाष्ट करना पड़े। पिता को तो बहुत काम करने पड़ते है। लेकिन मै आपसे यह कहना चाहता था मैडम कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को दिया गया और वे अपना-अपना टैक्स निर्धारित करती है। हम इसमें कैसे रोकेंगे उनको?

सेल्स टैक्स अलग है, प्राइस वह तय करते है। बिहार वालों का घाटा हो गया क्योकि उनकी सरकार ने बहुत देर से तय किया तो नही पहुंच सका। यह घाटा जरुर हुआ। इस बार हमने यह प्रयास किया है हम माननीय सदस्यों से कहना चाहते है यह यूरिया का सेल का पीरियड नही है। अब आगे आएगा। गेहूं की फसल भी अभी चली गई है। अब आगे आएगा। गेंहू की फसल भी अभी चली गई है। यूरिया देने की बात नही है। बहुत कम देना है। यह इसलिए हमने अभी दाम तय कर लिया। हरेक राज्य सरकार को और डी.एम. को गोडाउन के लिए लिख कर भिजवा रहे है और कंपनियों को कह रहे है कि ऑफ सीजन में जितना प्रोडक्शन होता है वह डिस्टैट एरिया में पह्ले ही जमा करके रख दें और पीक आवर्ज में हमको जो कहने लगते है कि आप स्पेशल ट्रेन दीजिए, यह दीजिए इससे झंझट होता है। इसलिए हमने लिखा है। बिहार के मुख्य मंत्री को लिखा है और दूसरों को भी लिखा है। लोग गोडाउन बना लें और अभी जो प्रोडक्शन होता है हम भेज देंगे तो आसानी से हम पहुंचा सकते है। यही मै कहूंगा ।

श्री नरेश यादव : मेरे सवाल का जवाब नही हुआ। मैंने कहा है पूरे देश में सेल टैक्स में समानीकरण होना चाहिए ।

श्री चतुरानन मिश्र : आप बताएं।

उपसभापति ; जवाब दे दिया ।

श्री चतुरानन मिश्र: जब पार्लियामेट में फ्री ट्रेड का तय कर लिया तो उसमें हम क्या करेंगे। आप लोगों ने सब कुछ तय किया है।

श्री राधवजी : महोदया, माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि आयात किया हुआ यूरिया बहुत महंगा पड़ता है और इसीलिए दाम बढाने की जरुरत पड़ती है। लेकिन इसके साथ-साथ कुप्रबन्ध भी है जिसके कारण दाम बढता है। जैसा भंडारी जी ने बताया कि समय पर माल बाहर से आयात होता नही है। जहाजों में खड़ा रहता है। पोर्ट में उत्तर जाता है।

उपसभापति : आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री राघवजी : मैडम, मेरा प्रश्न यह है कि इस कुप्रबन्ध को सुधारने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है ताकि किसानो को यूरिया जब आवश्यकता पड़े उस समय मिल जाए और आपकी भी कीमत लागत कम हो जाए इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे है/

श्री चतुरानन मिश्र : मैंने तो अभी कहा कि हरेक डी.एम. से कह रहे है कि पह्ले ही गोडाउन बना कर दे दे, वहां पहुचा देंगे। यह कुप्रबन्ध तो नही हुआ, यह तो सप्रबन्ध हुआ। उस दिशा में जा रहे है । अब पोर्ट वाला मामला कुछ टेढा है क्योकि पोर्ट की कैपोसिटी तो लिमिटेड है। फिर भी हम चाह रहे है कि पहले आ करके कर सकें।

श्री नगेद्र नाथ ओझा : महोदय, देश में यूरिया की कीमत की बात हो रही है। फर्टीलाइजर मिनिस्टर ने कहा कि एक ही मौसम में बुवाई के समय यूरिया की जरुरत होती है। कृषि मंत्री जी से हम यह जानना चाहेंगे कि बुवाई के समय ज्यादा जरूरत पड़ती है या सिचांई के समय या बुवाई के बाद, क्योकि फर्टिलाइजर मिनिस्टर कि बात देश को मालूम होने से बड़े अचम्भा में किसान पड़ेगें कि हमारे फर्टिलाइजर मिनिस्टर कहते है कि बुवाई के समय ही ज्यादा जरुरत पड़ती है। यह बेकार में कीमत की बात करने से क्या फायदा जब यही हमारे मंत्रियों का क्या कहना है?

श्री चतुरानन मिश्र : पता नही, हमने यह नही जाना कि फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने क्या कहा। हम तो ऐसा नही सुने है, लेकिन ऐसा होता है कि गेहूं की बुवाई के टाईम में डी.ए.पी. की पहले जरुरत हो जाती है उसको करते है और फिर थोड़े दिन के बाद यूरिया देते है तथा फिर पानी से उसको पटाते है। यह तो प्रोसैस रहता है। लेकिन एक स्टेज में आ करके जब उसमे दाना लगने लगे तब फिर हमको जरुर हो जाएगी। इसलिए यह लीन सीजन था जिसमे हमने यह इंतजाम कर दिया।

श्री राजनाथ सिंह सूर्य : माननीय उपसभापति जी, अभी मंत्री जी ने यह कहा है कि वह डिलिवरी का समय नही बता सकते, लेकिन जो हैड मैटरन है जिसके कि ये सब सहयोगी है उन्होंने जुलाई में यह कहा था कि गोरखपुर का खाद कारखाना तीन महीने में चालू हो जाएगा। तो उन्होंने डिलीवरी का समय भी बता दिया था तो भाई लोगों ने मिल करके उस समय डिलीवरी अब तक क्यों नही कराई क्या इसके बारे में कुछ बतायेंगे?

श्री चतुरानन मिश्र :यह पेरेन्ट्स से पूछिए। पेरेन्ट्स से पूछिए, वहां आप क्या बोले है। क्या अखबार में हम देखेंगे? और तीन महीने कहे हुए होंगे तो बात-चीत की जाएगी। ...(**व्यवधान**)... हो सकता है ...(**व्यवधान**)... यह तो आप समझ ही सकते है ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेन्द्र मोहन : पूरे ९ महीने हो गए है, मंत्री जी।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Qustion Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Inauguration of Breeder Seed Processing and Storage Complex in Kamal

*101. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether he had recently inaugurated in Kamal the Indian Agricultural Research Institute (IARI) breeder seed processing and storage complex for 'adding flavour to foodgrains with Japanese aid,' as reported in "The Hindustan Times" dated 4th February, 1997;

(b) if so, the details thereof, cost involved, grant-in-aid received from Japan, including supply of required instruments for testing hygienic conditions of Indian fruits, etc.; and

(c) whether such seed processing and storage complexes are likely to be set-up in Rajasthan and Orissa?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) The Seed Processing and Storage Complex at Indian Agricultural Research Institute's Regional Station, Karnal was inaugurated on 1.2.1997. This complex is primarily meant for improving the quality of nucleus / breeder seed of improved varieties of agri-horticultural crops using modern processing and storage techniques as well as buffer stocking of the same. The complex in not for 'adding flavour to foodgrains' as reported in the "Hindustan times" dated 4th February, 1997.

(b) The details of the project are given below:—

1. Cost involved:

(a) Japan Grant-in-Aid received=662 million Yen (Rs. 21.50 crores approx.)

(b) Indian Contribution=Rs. 15.50 lakhs (for renovation of building, laboratories and maintenance of equipments received under this project during 1996-97.

2. Equipments received:

The equipments received at Indian Agricultural Research Institute's Regional Station, Kamal and Division of Seed Science Technology, New Delhi under this project are primarily for seed processing, storage and research. Important equipments are given in Statement *(See* below).

For creating hygienic conditions in Indian fruits, the Government of Japan has assisted Agricultural Produce Export Development Agency (APEDA), under a separate project, in establishing a Vapour Heat Treatment (VHT) facility at the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi for research and pilot scale testing of the use of this facility for dis-infestation (creating hygienic conditions) of mangoes and other fruits against fruitflies to promote export of these fruits.

(c) No, Sir.

Statement

Equipments received under the Japanese Grant-in-Aid at lari Regional Station, Kamal.

1. *Processing & storing on field crops*

(i) Pre-cleaner;

(ii) Screen Grader;

(iii) Length separator;

(iv) Gravity Separator;

(v) Seed Treater;